

जोहार छत्तीसगढ़

दैनिक हिन्दी

वर्ष: -15 अंक: 277 डाक पंजीयन 030/रायगढ़/2015-2017 मूल्य: 3 ₹ पृष्ठ: 8



पेज -4 पर खेल तन और मन दोनों को स्वस्थ रखता, खेल प्रतिभागों को आगे बढ़ाने...

धरमजयगढ़, मंगलवार 1 अगस्त 2023

कांग्रेस की वादाखिलाफी की वजह से गई संविदाकर्मों की जान- ओपी चौधरी

पेज -8 पर

JOHAR CHHATTISGARH epaper for login www.joharchhattisgarh.in

निर्धारित प्रक्रिया के पालन बिना विकास की कहानी मनगढ़ंत

जोहार छत्तीसगढ़- धरमजयगढ़। किसी भी विकास परियोजना के क्रियान्वयन के लिए शासन द्वारा निर्धारित नियम कानून के पालन की अनिवार्यता तय की जाती है। यह इसलिए कि पारदर्शिता के साथ विकास कार्य का संचालन किया जा सके।

निश्चित रूप से ऐसे कार्यों में स्थानीय समुदाय के हित निहित होते हैं जो कि हर परियोजना का अनिवार्य हिस्सा होता है। यह अलग बात है कि कई अन्य उद्योग समूहों द्वारा ग्रामीणों को रोजगार व अन्य निर्धारित सुविधाएं मुहैया कराने का दावा किया गया लेकिन दशकों बाद भी प्रभावित अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। विकास का एक रूप ऐसा भी है जिसमें क्षेत्र का राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने वाले दिग्गजों के क्षेत्र के ग्रामीण

मलका के महाप्रबंधक का खोखला दावा और प्रयोजित प्रचार की हकीकत



आज भी अपने अधिकारों के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। बहरहाल हम बात कर रहे हैं धरमजयगढ़ में प्रस्तावित एक लघु जल विद्युत परियोजना की। जिसके लिए प्रभावित क्षेत्र में तेजी से काम चालू हो गया है। पानी से बिजली उत्पादन करने के इस बड़े प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन मलका रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा किया जा रहा है। बता दें कि शासन द्वारा निर्धारित नियमों के तहत इस प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिली है लेकिन अब इस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के बारे में तय किये गए नियम व शर्तों को लेकर मलका कंपनी व स्थानीय

प्रशासन द्वारा अलग-अलग बातें कही जा रही हैं। इस प्रोजेक्ट में प्रभावित किसानों के हितों की अनदेखी करने के मामले में पिछली रिपोर्ट में हमने बताया था कि बिना किसी वैध प्रक्रिया के कंपनी निजी जमीन का उपयोग कर रही है। जिसके संबंध में धरमजयगढ़ एसडीएम डिगेश पटेल ने तब बताया था कि कंपनी द्वारा प्रभावित निजी जमीन की खरीदी की जाएगी। कथनी और करनी में अंतर इस मामले पर पूर्व में की गई एक रिपोर्ट प्रकाशन के बाद कंपनी के महाप्रबंधक के हवाले

से किए गए इस दावे के साथ दूसरी खबर आई कि नियमानुसार प्रभावित किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इस खबर में कंपनी का समर्थन करने वाली कुछ अन्य बातों का भी उल्लेख किया गया। लेकिन इसमें



सबसे महत्वपूर्ण व तीसरे पक्ष यानी स्थानीय प्रशासन को शामिल नहीं किया गया। ऐसे में यह संबंधित कंपनी का प्रयोजित प्रचार-प्रसार का एक मामूली प्रयास मात्र लगता



है। यह कंपनी के महाप्रबंधक द्वारा भूमि अधिग्रहण के कथित दावे को इसलिए भी हल्का करता है क्योंकि इस प्रायोजित गुणगान में स्थानीय प्रशासन के आला अधिकारी का पक्ष रखने से परहेज किया गया। तो यह हैरान करने वाली स्थिति है जिसमें किसी भी संबंधित व जिम्मेदार पक्ष को यह ठीक ठीक पता नहीं है कि वास्तव में परियोजना से संबंधित निजी जमीन के उपयोग के संबंध में किस तरह की प्रक्रिया का पालन किया जाना है। यह अविश्वसनीय है कि बिना किसी

निर्धारित प्रक्रिया के एक बड़े परियोजना का काम शुरू कर दिया जाता है और संबंधित कंपनी के कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। ऐसा इसलिए कि एक ओर मलका कंपनी के महाप्रबंधक के हवाले से यह बताया जा रहा है कि प्रभावित किसानों की जमीनों का अधिग्रहण शासन के नियमों के मुताबिक किया जाना है जबकि इसके उलट यह बात सामने आई है कि कंपनी द्वारा जमीन की खरीदी की गई है। संबंधित विभाग के एक जिम्मेदार ने कंपनी द्वारा जमीन खरीदे जाने की पुष्टि की है।

प्रक्रिया को लेकर बढ़ रहा संशय

इस प्रकार यह मामला और पेचीदा होते जा रहा है जिसमें यह तय कर पाना मुश्किल हो रहा है कि निजी जमीन की खरीदी होगी या अधिग्रहण। दोनों प्रक्रियाओं के लिए अलग-अलग नियम कानून बने हुए हैं। तो प्रयोजित प्रचार के रूप में कंपनी का यशोगान करने के फेर में इस बात को बुरी तरह नजर अंदाज किया गया है कि जब किसी कार्य के लिए निर्धारित मापदंड स्पष्ट नहीं होते हैं तो उसे किसी भी पैमाने पर विकास के रूप में नहीं देखा जा सकता है। यह कहना गलत है कि कंपनी लगने से क्षेत्र का विकास नहीं होगा। बिल्कुल होगा, लेकिन जब तक यह बात स्पष्ट नहीं हो जाती कि विकास किन मापदंडों से होकर गुजरेगा, तब तक उसे अंधाधुन विकास के रूप में ही पहचाना जाता रहेगा। यह भी कि विकास नितांत आवश्यक है लेकिन प्रभावित किसानों की जमीनों को लेकर अविश्वसनीय वर्तमान को देखते हुए इस प्रोजेक्ट से लोगों के सुनहरे भविष्य का कपटल कल्पित और प्रयोजित प्रोपेण्डा न केवल क्षामक बल्कि विषुद्ध रूप से मनगढ़ंत भी लगता है। बेहतर होगा कि प्रशासन व मलका कंपनी आपस में मिलकर पहले यह तय कर लें कि अखिर प्रभावित किसानों के हित के लिए किन निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करना है।



एक नजर

छत्तीसगढ़ में चुनाव के लिए कांग्रेस के ऑब्जर्वर नियुक्त

प्रीतम सिंह को सीनियर ऑब्जर्वर और मीनाक्षी नटराजन को ऑब्जर्वर बनाया गया



रायपुर। छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में इस साल विधानसभा चुनाव होगा। जिसको लेकर कांग्रेस हाईकमान ने इन पांचों राज्यों में ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ में ये जिम्मेदारी कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह और मीनाक्षी नटराजन को मिली है। विधानसभा चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर प्रीतम सिंह को बनाया गया है जबकि मीनाक्षी नटराजन को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ के अलावा मध्यप्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में भी ऑब्जर्वर बनाए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय बालगंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर किया नमन

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं समाज सुधारक श्री बालगंगाधर तिलक की एक अगस्त को पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है।

शराब घोटाले के आरोपियों पर नोएडा में एफआईआर

अनवर डेबर समेत 2 आईएएसअफसरों, एपी त्रिपाठी और हेलेोग्राम कारोबारी पर केस दर्ज

रायपुर। शराब घोटाला मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। प्रवर्तन निदेशालय के डिप्टी डायरेक्टर हेमंत कुमार ने नोएडा के कासना थाना में शराब घोटाले के आरोपियों पर एफआईआर दर्ज करवाई है। अब नोएडा की पुलिस इन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।



को पता चला कि नोएडा स्थित आरोपी विधु गुप्ता की कंपनी मेसर्स प्रिन्स हेलेोग्राफी सिक्वोरिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड को अवैध तरीके से खड़ा किया गया। इसे गलत तरीके से छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग को हेलेोग्राम की आपूर्ति के लिए टेंडर दिया गया। इस कंपनी के मालिकों, राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों का काम किया। इसमें अरुणपति त्रिपाठी आईटीएस (विशेष सचिव उत्पाद शुल्क), निरंजन दास आईएएस (आबकारी आयुक्त), समेत एक और IAS निविदा से चुड़ी प्रक्रिया को मॉनिटर कर रहे थे। इन्होंने ही टेंडर कंपनी को दिया। बदले में, उन्होंने प्रति हेलेोग्राम 8 पैसे का कमीशन लिया। नोएडा में डुप्लीकेट हेलेोग्राम बनाने वाले कारोबारी गुप्ता ने ED की जांच में बताया कि अरुण पति त्रिपाठी मुझे टेलीफोन पर कई सीरियल नंबर देते थे, ये हेलेोग्राम की संख्या वो होती थी जो पहले ही मुद्रित की जा चुकी है और उत्पाद शुल्क को आपूर्ति की जा चुकी है। इसके बाद फर्जी हेलेोग्राम बनते थे। इसे शराब की बोतलों पर लगा दिया जाता था। इससे राज्य के खजाने को 1200 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ और आरोपियों को अवैध लाभ हुआ।

मिनीमाता की पुण्यतिथि पर छग आएं खड़गे

रायपुर। कांग्रेस के विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत जांजगीर-चांपा से हो सकती है। 11 अगस्त को मिनीमाता की पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा के साथ बैठक में कहा था कि राष्ट्रीय



जांजगीर आ सकते हैं। विधानसभा चुनाव की दृष्टि से अविभाजित जांजगीर जिले की छह में सिर्फ दो सीट पर कांग्रेस विधायक हैं। बाकी दो सीट पर भाजपा और दो सीट पर बसपा विधायक हैं। ऐसे में कांग्रेस खरगे से चुनाव प्रचार अभियान की जांजगीर से शुरुआत करके अनुसूचित जाति बहुल विधानसभा

क्षेत्र के वोटों को साधने की फिराक में है। प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए दस विधानसभा सीटें आरक्षित हैं। वर्तमान में सात पर कांग्रेस, दो पर भाजपा और एक सीट पर बसपा के विधायक हैं। कांग्रेस ने एएससी वोटों को साधने के लिए हर ब्लाक में जैतखाम बनाने की घोषणा की है।

फांसी लगाने से हुई थी रशियन महिला की मौत

पीएम रिपोर्ट आया सामने, कारण बना रहस्य



रायपुर। राजधानी रायपुर के पंडरी थाना क्षेत्र में दस दिन पहले किर्गिस्तान की रहने वाली 25 वर्षीय नीना बिन्दनेको द्वारा अशोका रॉस के प्लेटे की बालकनी में फांसी लगाकर खुदकुशी करने का मामला अब रहस्य बना हुआ है। पुलिस को अब जाकर विदेशी महिला के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली है जिसमें हेंगिंग से मौत होने का उल्लेख डाक्टरों ने किया है। इससे साफ है कि महिला ने खुदकुशी की थी लेकिन उसने

आत्मघाती कदम क्यों उठाया यह सवाल उठने लगा है। विदेशी एंबेसी और स्वजनों से संपर्क के बाद पुलिस ने महिला के शव को हफ्ते दिन पहले किर्गिस्तान भिजवाया था। महिला की मौत की वजह अब तक पुलिस नहीं खोज सकी है। इमरान फारूखी से वह कैसे मिली इस बात पर भी पुलिस ने परदा डाल रखा है। उल्लेखनीय है कि खुदकुशी करने के पहले विदेशी महिला ने पहले दोस्त इमरान फारूखी को वाट्सएप से वीडियो संदेश भेजा था। दोनों की दोस्ती इंटरनेट मीडिया के माध्यम हुई थी। एक वर्ष पहले वह रायपुर आई थी। वह टैटू आर्टिस्ट थी।

न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी बने बिलासपुर हाई कोर्ट के स्थाई जज

चीफ जस्टिस श्री रमेश सिंह ने दिलायी शपथ



रायपुर। मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा ने आज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कोर्ट हाल नम्बर 1 में आयोजित एक गरिमामय कार्यक्रम में न्यायमूर्ति श्री दीपक कुमार तिवारी को स्थायी जज के रूप में शपथ दिलाई। उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति श्री दीपक कुमार तिवारी की नियुक्ति 08 अक्टूबर 2021 को एडिशनल जज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में हुई थी। विधि एवं विधायी कार्य विभाग, नई दिल्ली द्वारा 28 जुलाई

2023 को न्यायमूर्ति श्री दीपक कुमार तिवारी को स्थायी जज में नियुक्ति संबंधी अधिसूचना जारी की गयी थी। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में समस्त न्यायमूर्तिगण रजिस्ट्री व ज्यूडिशियल एकेडमी के न्यायिक अधिकारीगण, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर, प्रमुख सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, रायपुर अधिवक्तागण एवं न्यायमूर्ति श्री दीपक कुमार तिवारी के परिवार के सदस्य उपस्थित थे।

समीक्षा बैठक...

सभी निर्माण एजेंसिया आपस में समन्वय बनाकर करें सड़कों का निर्माण

बारिश के बाद सड़कों की त्वरित गति से करें मरम्मत: मुख्यमंत्री

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को बारिश खत्म होने के तुरंत बाद सड़कों की मरम्मत करवाने के निर्देश दिए हैं।



मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा है कि आम जनता के सुविधा के लिए सड़कों के अंधरे कार्य, सड़कों की मरम्मत और नवीनीकरण के कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में सड़क निर्माण के कार्य में लगी सभी एजेंसियों को



आपस में सामंजस्य बनाकर तेजी से काम करना है। मुख्यमंत्री ने समीक्षा के दौरान रायपुर शहर के चार महत्वपूर्ण कार्यों की भी जानकारी ली। इसमें तेलीबांधा में फ्लाइओवर का निर्माण, शारदा चौक से ताल्यापारा चौक तक सड़क निर्माण, अटल एक्सप्रेस वे से वीआईपी रोड निर्माण तथा

मुख्यमंत्री ने की लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा

खारून रिवर फ्रंट के निर्माण कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने विशेष तौर पर शारदा चौक से ताल्यापारा चौक तक निर्माण तथा भू-अर्जन प्रकरण समेत लगभग 137 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 510 मीटर लंबी सड़क को लेकर अधिकारियों को निर्देश देते हुए जल्द ही इसका कार्य शुरू

एक्सप्रेस वे को वीआईपी रोड से जोड़ने वाले ओवरब्रिज के बारे में भी अधिकारियों से समीक्षा की। बैठक में लोक निर्माण विभाग मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, शिक्षा मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, नगरीय प्रशासन विभाग के विशेष सचिव श्री अयाज भाई तंबोली, सीजीआरआईडीसीएल के प्रबंध संचालक श्री सारांस मित्र एवं लोक निर्माण विभाग के ईएनसी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ में राज्य प्रशासनिक सेवा के 23 अफसरों के तबादले

शैलाभ साहू दुर्ग RTO, मुकेश कोठारी डिप्टी कलेक्टर रायपुर बनाए गए

रायपुर। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक सचर्री का दौर जारी है। सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 23 अफसरों का तबादला आदेश जारी किया है। जिसमें रायपुर RTO की जिम्मेदारी सम्भालने वाले शैलाभ साहू को दुर्ग की जिम्मेदारी दी गई है। मुकेश कोठारी डिप्टी कलेक्टर रायपुर बनाए गए हैं। इसी तरह वीरन्द्र सिंह को राजनांदगांव RTO की जिम्मेदारी दी गई है।



अफसर का नाम	नया पद	पुराना पद
शैलाभ साहू	दुर्ग RTO	रायपुर RTO
मुकेश कोठारी	रायपुर डिप्टी कलेक्टर	दुर्ग डिप्टी कलेक्टर
वीरन्द्र सिंह	राजनांदगांव RTO	दुर्ग RTO

